

प्रेषक,

सौरभ जैन,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2 :

देहरादून: दिनांक- 29 मार्च, 2008

विषय:- जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के उप मिशन बी०एस०यू०पी० के अन्तर्गत नैनीताल शहर के दुर्गापुर में आवास तथा अन्य अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक तथा व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या N-11026/2/2008/BSUP/JNNURM-Vol. IV दिनांक 7-3-2008 के द्वारा केन्द्रीय संस्तुति एवं मानिट्रिंग कमेटी (सी०एस०एम०सी०) की 32वीं बैठक दिनांक 27-2-2008 में संलग्न कार्यवृत्त के अनुरूप नैनीताल शहर के दुर्गापुर में आवास तथा अन्य अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण हेतु कुल धनराशि रु० 930.04 लाख की डी०पी०आर० संस्तुति की गयी है। तत्क्रम में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के पत्र संख्या 59(16)/P.F.-1/2007-307 दिनांक 17-3-2008 द्वारा उक्त योजना हेतु प्रथम चरण के लिए केन्द्रांश की धनराशि रु० 185.65 लाख अवमुक्त की गयी है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त के विपरीत केन्द्रांश के रूप में रु० 185.65 लाख तथा इस धनराशि के सापेक्ष देय राज्यांश रु० 46.86 लाख के विपरीत आवास विभाग के शासनादेश संख्या 2410/V/आ०-2007-57(सा०)/2003 दिनांक 30-11-2007 के द्वारा रईस होटल कम्पाउण्ड में अवस्थित परिवारों को दुर्गापुर में आवास बनाने हेतु स्वीकृत रु० 140.13 लाख को इस धनराशि में कम करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि के विपरीत देय अवशेष केन्द्रांश व राज्यांश के बराबर रु० 92.38 लाख (रु० बयानवें लाख अड़तीस हजार मात्र) की अवशेष धनराशि को आई०एच०एस०डी०पी० के संलग्न बी०एम०-15 में उल्लिखित अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों के व्ययवर्तन के द्वारा व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि आपके द्वारा आहरित कर सम्बन्धित नगर पालिका परिषद, नैनीताल को बैंक ड्राफ्ट अथवा चेक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी और उनके द्वारा डी०पी०आर० की व्यवस्थानुसार कार्यदायी संस्था का चयन होने पर इस धनराशि को उक्त संस्था को अवमुक्त कर दिया जायेगा। इस धनराशि को उक्त के अलावा किन्हीं अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं किया जायेगा।

2. अध्यक्ष, झील विकास प्राधिकरण, नैनीताल द्वारा उपरिलिखित शासनादेश दिनांक 30-11-2007 के द्वारा स्वीकृत धनराशि का यदि उपयोग नहीं किया गया है तो इस धनराशि का आहरण कर नगर पालिका परिषद को उपलब्ध करा दिया जायेगा और यदि धनराशि का उपयोग कर लिया गया है तो अवशेष धनराशि को नगर पालिका परिषद, नैनीताल को स्थानान्तरित कर दी जायेगी। जो धनराशि उपयोग की जा चुकी है उसे आवास विभाग के शासनादेश संख्या 454/V-आ0-2008-57(सा0)/2003 दिनांक 27-3-2008 के अनुसार इसकी प्रक्रिया जे0एन0एन0यू0आर0एम0 से की जायेगी।
3. उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं एवं मदों के लिए किया जायेगा जिन योजनाओं एवं मदों के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। किसी भी दशा में धनराशि का व्ययवर्तन किसी अन्य योजना/मद में नहीं किया जायेगा।
4. भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत उक्त योजना के कार्यों हेतु यह अवश्य सुनिश्चित किया जाय कि उक्त कार्य हेतु राज्य सरकार के बजट से धनराशि न दी गयी हो, यदि दी गयी हो तो उस धनराशि को इस अनुमोदित लागत के सापेक्ष व्यय दिखाकर विभागीय बजट से स्वीकृत बजट को शासन को समर्पित कर दिया जाय।
5. उक्त धनराशि को नगर पालिका परिषद, नैनीताल को अवमुक्त किये जाने से पूर्व नगर पालिका परिषद के साथ MoA हस्ताक्षरित करते हुए शासन की सहमति प्राप्त कर ली जायेगी।
6. जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत उप मिशन बी0एस0यू0पी0 की भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
7. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय द्वारा जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत अपेक्षित सुधारों के पृथक-पृथक प्रस्ताव तैयार कर शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।
8. स्वीकृत धनराशि के व्यय अथवा निर्माण करने से पूर्व सभी योजनाओं/कार्यों पर संबंधित मानचित्र एवं विस्तृत आगणन गठित कर तकनीकी दृष्टिकोण से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए एवं विशिष्टियों का अनुपालन करते हुए प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
9. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करानी होगी। जिसमें कि भौतिक प्रगति का स्पष्ट उल्लेख होगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी और उसके अभियंता पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे।
10. स्वीकृत कार्य कराते समय द्वितीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर परचेज रूल्स एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये, एकमुश्त प्राविधान के विस्तृत आगणन गठित कर लिये जायें, और इन पर यदि किसी तकनीकी अधिकारी के कार्य कराने से पूर्व का अनुमोदन प्राप्त करना नियमानुसार आवश्यक हो तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।
11. आगणन में उल्लिखित दरों को विश्लेषण सम्बन्धित विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को पुनः स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
12. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

13. कार्य पूर्ण होने पर इसे वित्तीय वर्ष में उक्त कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण राज्य सरकार को तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र भी राज्य सरकार एवं भारत सरकार को प्रेषित करा दिया जायेगा। योजना के लिए स्वीकृत धनराशि का मासिक व्यय विवरण भी शासन को प्रेषित किया जायेगा।
14. कार्य को भारत सरकार के द्वारा दी गई प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति की सीमा के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा। इस लागत में कोई वृद्धि वित्त पोषण के पैटर्न से इतर राज्य सरकार के द्वारा अनुमन्य नहीं होगी।
15. उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष-2007-08 के आय-व्यय के अनुदान सं०-13, लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-06-बेसिक सर्विसेज टू अरबन पुअर्स योजना-20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता के नामे डाला जायेगा।
16. यह आदेश वित्त विभाग के अशा०सं०- 402/XXVII(2)/2008, दिनांक- 29 मार्च, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सौरभ जैन)
अपर सचिव।

सं० भा०सं०-23 (1)/IV(2)-शा०वि०-08, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निजी सचिव, मा० नगर विकास मंत्री जी (मा० मुख्यमंत्री जी)।
- 3- आयुक्त, कूमायू मण्डल, नैनीताल।
- 4- अध्यक्ष, झील विकास प्राधिकरण, नैनीताल।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- 6- जिलाधिकारी, नैनीताल।
- 7- वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- ✓ 8- निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी०ओ० में इसे शामिल करें।
- 9- प्रशासक/अधिकांसी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नैनीताल।
- 10- बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 11- गार्ड बुक।

आज्ञा से,


(अनूप सिंह)
अनु सचिव।